जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 171 प्रभात चूरू, शुक्रवार 17 अक्टूबर, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

भारत व भारत के मित्र राष्ट्रों में अविश्वास व कंफ्यूज़न फैलाना चाह रहे हैं ट्रंप

इसके लिए ट्रंप ने माध्यम बनाया है, भारत द्वारा रूस से पैट्रोलियम की खरीद को

- ट्रंप ने कहा कि मोदी ने टेलीफोन करके उन्हें विश्वास दिलाया है कि वे रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं, बंद करने की प्रक्रिया में कुछ समय लग रहा है।
- इसलिए विलंब तो हो रहा है, किन्तु अंततोगत्वा खरीदी बंद हो जाएगी।
- भारत ने तुरंत ट्रंप के इस दावे को खारिज किया कि मोदी ने कोई ऐसा आश्वासन ट्रंप को दिया है।
- रूस ने भी वक्तव्य दिया कि वह कभी भी अपने खरीददार की एनर्जी पर्चेज़ में दखल नहीं देता है।
- रूस ने यह भी कहा कि, भारत और रूस के रिश्ते आपसी सहयोग की नींव पर बने हैं, रूस का तेल भारत के हित में था, जब तेल का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट अस्त-व्यस्त हो रहा था।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर। डॉनल्ड ट्रम्प ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें टेलीफ़ोन पर आश्वासन दिया कि भारत जल्द ही रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा।

यूक्रेन में रूस के युद्ध पर नियंत्रण पाने में असमर्थ और रूस को घेरने की अमेरिकी कूटनीतिक कोशिशों के पूरी तरह विफल होने के बाद, ट्रम्प अब अविश्वास और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण भारत के रुख में आये बदलाव के बारे में अचानक बयानबाजी हो रही है।

ट्रम्प का कहना है कि मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत के लिए रूसी तेल व्यापार को रोकना केवल एक प्रक्रिया है, जिसमें समय लगता है।

भारत ने ट्रंप के दावों पर बहुत सावधानी से प्रतिक्रिया दी है और प्रधानमंत्री की ओर से ऐसी किसी भी संभावना या आश्वासन को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है।

विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर ट्रम्प के बयानों को ग़लत बताया और स्पष्ट किया कि भारत की तेल खरीद केवल एक उद्देश्य से प्रेरित है, अपने नागरिकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और भविष्य में भी मार्गदर्शक सिद्धांत यही रहेगा।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि ऊर्जा उत्पादों की स्थिर कीमतें बनाए रखना और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना भारत की ऊर्जा नीति के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। भारत ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रहा है और अन्य देशों के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ा रहा है।

मामले ने तब और तूल पकड़ा, जब ट्रम्प ने कुछ अनौपचारिक बातचीत में दावा किया कि उन्होंने मोदी से फ़ोन पर बात की थी और तभी भारत की ओर से यह आश्वासन दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी उनके विश्वसनीय मित्र हैं और वो ट्रम्प से प्यार करते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या, आरोपियों को फांसी

आगरा, 16 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश में आगरा जिले की एक विशेष अदालत ने पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को फांसी की सज़ा सुनायी है।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने 18 गवाह और कई बार की हुई बहस के बाद गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। घटना 18 मार्च 2024 को थाना बाह इलाके की है।

- घटना 18 मार्च की है। पॉक्सो कोर्ट में 18 गवाहों के बयानों व कई बहसों के बाद जज सोनिका चौधरी ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई।

दोनों आरोपियों ने पांच साल की बच्ची का पहले अपहरण किया, उसके बाद दुष्कर्म करके हत्या की थी। सजा सुनाये जाने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष गिरी ने बताया कि दोपहर तीन बजे बच्ची रास्ते में खेल रही थी, तभी दोनों आरोपी अमित और निखिल मोटर साइकिल से आए और बच्ची को उठा ले गए। दोनों ने नहर किनारे ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म किया और हत्या करके शव को सरसों के खेत में फेंक दिया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विकासशील इंसान पार्टी के साथ बहुत बुरी हुई, महागठबंधन के बँटवारे में

पार्टी ने साठ सीटों की माँग की थी व अपने नेता के लिए मंत्री पद

- उन्होंने स्वयं अपनी माँग घटाकर चालीस की और फिर तीस और फिर तेजस्वी यादव ने पंद्रह सीट का ऑफर दिया।
- पर शर्त यह रखी कि पंद्रह में से नौ सीटों के उम्मीदवार आरजेडी ही तय करेगी।
- तिरस्कृत विकासशील इंसान पार्टी के नेता सहनी ने महागठबंधन से नाता तोड़ने का ऐलान करने के लिए प्रैस कॉन्फ्रैंस बुलाई।
- पर, हर बार महागठबंधन के किसी न किसी बड़े नेता ने हस्तक्षेप करके घोषणा टलवाई और अंत में सहनी लटकते ही रह गए।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से एक दिन पहले, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नेता मुकेश सहनी की प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर पूरे दिन सस्पेंस और हाई ड्रामा बना रहा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कथित रूप से आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से उनके अलग होने की घोषणा के लिए बुलाई जानी थी। कॉन्फ्रेंस के लिये, पहले दोपहर 12 बजे का समय तय किया गया था, फिर उसे 4 बजे तक टाल दिया गया और अंततः शाम 6 बजे के बाद आयोजित करने की बात कही गई।

इस बीच घटनाक्रमों का सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सहनी को फोन कर उनके हितों का ध्यान रखने का भरोसा दिलाया। आरजेडी ने अपने एक वरिष्ठ नेता को नई दिल्ली भेजा, ताकि कांग्रेस के नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक की जा सके। कांग्रेस ने भी केन्द्रीय चुनाव समिति की एक आपात बैठक बुलाई।

एनडीए की ही तरह, महागठबंधन भी कागज़ों पर तो एकजुट है, लेकिन सहयोगी दल आपस में कई सीटों को लेकर टकराव की स्थिति में हैं। उदाहरण के लिए, कांग्रेस और सीपीआई (एमएल) दोनों ने एक ही सीट पर अपने-अपने उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए हैं। दरभंगा की जाले सीट और सीमांचल क्षेत्र की कई अन्य सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच मतभेद बने हुए हैं।

सबसे खराब स्थिति मुकेश सहनी के हिस्से में आई है। उन्होंने सीट बंटवारे की बातचीत की शुरुआत ऊँचे स्वर में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जैसलमेर बस अग्निकांड में बस मालिक व ड्राइवर गिरफ्तार

मुख्यमंत्री ने मृतक के आश्रितों को दस-दस लाख रूपये की सहायता देने के निर्देश दिये

- जोधपुर में बस बॉडी बनाने वाले कारखाने के मालिक मनीष जैन से पुलिस पूछताछ कर रही है कि बस बॉडी निर्माण में निर्धारित बॉडी कोड मानकों का पालन हुआ या नहीं।
- गुरुवार सुबह एक और यात्री, 54 वर्षीय भागा बानो की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

जैसलमेर, 16 अक्टूबर (नि.सं.)। जैसलमेर बस अग्निकांड में पुलिस ने बुधवार रात बस मालिक तुराब अली और ड्राइवर शौकत को गिरफ्तार कर लिया। एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। जोधपुर में बस बनाने वाले कारखाने के मालिक मनीष जैन को जैसलमेर पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस हृदय विदारक घटना को लेकर घोषणा की है कि मृतकों के आश्रितों को दस दस लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही जिस परिवार में तीन या अधिक मौतें हुई हैं उन्हें 25-25 लाख की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल लोगों को दो-दो लाख और अन्य घायलों को एक- एक लाख की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

जैसलमेर पुलिस बस कारखाने के मालिक मनीष जैन को पूछताछ के लिए जैसलमेर लाई है। बस की तकनीकी खामियों को लेकर मनीष जैन से पूछताछ की जायेगी। मनीष जैन जोधपुर स्थित जैन ट्रेवल्स के भी मालिक हैं। जैन ट्रेवल्स की बसें बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर में चलती हैं।

परिवहन विभाग की टीम ने बस की बॉडी बनाने वाली कंपनी जैनम कोच क्राफ्टर के जोधपुर परिसर में तैयार हो रही 66 बसों को जब्त कर लिया है। टीम यह भी जांच करेगी कि बस बॉडी निर्माण के दौरान निर्धारित बॉडी- कोड मानकों का पालन हुआ है या नहीं।

इस भीषण अग्निकांड में मृतकों की संख्या 22 हो गई है। 54 साल की भागा बानो की गुरुवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई।

इधर जोधपुर में डीएनए परीक्षण एवं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण होने पर जोधपुर एम्स व महात्मा गांधी अस्पताल में रखे 18 शव उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक शव को पूर्ण सम्मान एवं संवेदनशीलता के साथ उनके पैतृक गांव

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गुजरात में आज मंत्रिमंडल फेरबदल

गांधीनगर, 16 अक्टूबर। गुजरात की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार के कुल 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि गुजरात में भाजपा सरकार कैबिनेट का विस्तार करने जा रही है। सामने आई जानकारी

- गुरुवार को गुजरात सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया।

के मुताबिक, शुक्रवार को दोपहर 12 बजकर 39 मिनट पर गुजरात सरकार के नए मंत्रिमंडल का शपथ समारोह का आयोजन होगा।

इस फेरबदल को राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक, गुजरात की भाजपा सरकार के कैबिनेट विस्तार में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दस में से सात अमेरिकी मानते हैं कि अमेरिका में उच्च शिक्षा गलत दिशा में जा रही है

इन लोगों का मानना है कि उच्च शिक्षा बहुत महँगी है, बहुत कट्टर विचारधारा पनपाती है और विद्यार्थियों को असली दुनिया में सफलता पाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं करती

- दोनों मुख्यधारा की पार्टियाँ, डैमोक्रेट और रिपब्लिकन, इस बारे में एकमत हैं कि उच्च शिक्षा की दशा व दिशा बदलनी चाहिए।
- पर इन दोनों पार्टियों के नेताओं में भारी मतभेद है कि यह खराब स्थिति कब और किन कारणों से पैदा हुई है।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर। कभी दुनिया में "स्वर्ण मानक" माने जाने वाले अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थान अब बढ़ते अविश्वास के संकट का सामना कर रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के एक नए सर्वेक्षण के अनुसार, 10 में से 7 अमेरिकी (लगभग 70 प्रतिशत) मानते हैं कि देश के कॉलेज और विश्वविद्यालय "गलत दिशा" में जा रहे हैं - यह 2020 के 56 प्रतिशत के आंकड़े की तुलना में तीव्र बढ़ोतरी दर्शाता है। कभी राष्ट्रीय गौरव और अवसर के प्रतीक रहे विश्वविद्यालय अब अत्यधिक महंगे, वैचारिक रूप से कठोर और वास्तविक जीवन में सफलता की तैयारी में अक्षम माने जा रहे हैं।

22 से 28 सितंबर, 2025 के बीच 3,445 अमेरिकी वयस्कों पर किए गए एक सर्वेक्षण पर आधारित ये निष्कर्ष "द्विदलीय सहमति" एक दुर्लभ बिन्दू देखने को मिला यह था मोहभंग। उम्र, आय और राजनीतिक पहचान से परे, अधिकांश अमेरिकियों का मानना है कि देश की उच्च शिक्षा प्रणाली में कुछ बुनियादी खामियां है। हालांकि, इस साझा असंतोष के कारण राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार अलग-अलग हैं।

सर्वेक्षण का समय भी राजनीतिक रूप से अहम है। हाल ही में ट्रम्प प्रशासन ने विश्वविद्यालयों पर निगरानी कड़ी करने के कदम उठाए हैं - नौ संस्थानों से यह अपेक्षा करते हुए कि वे संघीय फंड्स तक विशेष पहुंच के बदले कुछ नीतिगत बदलाव करें। इस प्रस्ताव ने शिक्षा जगत में सरकारी हस्तक्षेप को लेकर बहस छेड़ दी है।

अमेरिकियों की असंतुष्टि लगभग हर पहलू में झलकती है। लगभग 79 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय ट्यूशन फीस को किफायती बनाए रखने में "सामान्य या खराब" प्रदर्शन कर रहे हैं - जो छात्रों और परिवारों के लिए सबसे बड़ी चिंता है। कॉलेज में पढ़ाई की औसत वार्षिक लागत अब 30,000 से अधिक हो चुकी है, जिससे बहुत से लोग खुद को उस सीढ़ी से बाहर महसूस कर रहे हैं जो कभी आर्थिक उन्नति का सबसे सुनिश्चित रास्ता मानी जाती थी।

खर्च वहन करने से आगे, अब विश्वविद्यालयों के "मूल उद्देश्य" पर भी सवाल उठ रहे हैं। आधे से अधिक वयस्कों (55 प्रतिशत) का मानना है कि कॉलेज छात्रों को अच्छी नौकरियों के लिए तैयार करने में कमजोर हैं, जबकि 52 प्रतिशत कहते हैं कि वे ज़रूरतमंद छात्रों को पर्याप्त आर्थिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केरल में सिर्फ दो घंटे पटाखे चलने की अनुमति

तिरुवनंतपुरम, 16 अक्टूबर। केरल में आगामी दिवाली पर सिर्फ दो घंटे हरित पटाखों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गयी है।

केरल के गृह विभाग ने दिवाली के दौरान पटाखों और संबंधित विस्फोटकों

- केरल के गृह मंत्रालय ने कहा दो घंटे में भी सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकते हैं।

के उपयोग के संबंध में नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के अनुसार जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किये जाने के निर्देश दिए हैं।

गृह विभाग के निर्देश में कहा गया है कि केवल हरित श्रेणी के पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी तथा इसके लिए समय सीमा दो घंटे रात आठ बजे से 10 बजे तक निर्धारित की गयी है।

'कोटपुतली नगर निगम ने जानबूझकर गोलमोल जवाब दिया, जिससे यह साफ नहीं होता कि सड़क चौड़ी करने की प्रक्रिया में कानून का पालन किया गया था या नहीं'

हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत अंतिम निर्णय सुनाने से पूर्व सरकार को नया जवाब देने का अवसर देना चाहती है

- कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.पी. शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 नवम्बर की तारीख दी है।
- यह मामला वर्ष 2021 में कोटपुतली नगर पालिका द्वारा राजमार्ग नम्बर 8 से विवेकानंद स्कूल तक के रास्ते को चौड़ा करने के लिए सड़क किनारे के मकानों व दुकानों को तोड़े जाने से संबंधित है।
- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2023 में कोटपुतली को जिला बना दिया गया था, उससे कुछ अर्सा पूर्व वहाँ नगर परिषद की जगह नगर निगम बना दिया गया था।
- कोटपुतली नगर निगम ने अदालत में प्रस्तुत अपने जवाब में नगर परिषद की कार्यवाही सही ठहराने के लिए कोई दलील नहीं दी है।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 16 अक्टूबर। कोटपुतली में पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2021 में तत्कालीन नगर परिषद द्वारा अस्थाई अतिक्रमण हटाने के नाम पर करीब 150 मकानों को अवैध रूप से तोड़ने के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई कार्यकारी मुख्य न्यायधीश एस.पी. शर्मा और न्यायधीश बलजिंदर सिंह संधू के समक्ष हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कोटपुतली नगर निगम द्वारा प्रस्तुत जवाब पर कड़ी टिप्पणी की व कहा कि जवाब जान बूझ कर अस्पष्ट और गोलमोल दिया है और जवाब से कभी भी यह स्पष्ट नहीं होता कि तत्कालीन नगर निगम परिषद ने कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए 60 फीट चौड़ी सड़क को 80 फीट तक चौड़ी करने के लिए सही कानूनी प्रक्रिया अपनाई भी थी या नहीं क्योंकि सड़क की चौड़ाई बढ़ाने से पहले तत्कालीन नगर परिषद को उस सड़क के दोनों ओर रह रहे निवासियों और दुकानदारों को सूचित करना था , उनसे आपत्तियां आमंत्रित करने थे और तोड़ फोड़ करने से पूर्व उपयुक्त मुआवजा भी तय करना था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि तत्कालीन नगर निगम परिषद द्वारा तोड फोड की कार्यवाही प्रथम दृष्टया गैर कानूनी और बिना कानूनी मंजूरी के की गई है। अदालत ने कहा कि इस मामले में अपना अंतिम निर्णय सुनाने से पहले वह महाअधिवक्ता को अवसर देना चाहती है कि वह नया जवाब प्रस्तुत करे और दस्तावेज भी प्रस्तुत करे। अदालत ने इस मामले की अगली तारीख 6 नवंबर तय की है।

जैसा कि विदित है कि वर्ष 2021 में कोटपुतली नगर परिषद ने जयपुर दिल्ली के बीच बने राज मार्ग नंबर 8 से विवेकानंद स्कूल तक जा रहे लम्बवत रस्ते पर करीब 150 मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया था। इस कार्यवाही के पूर्व कई याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अंतरिम रोक के लिए गुहार करी थी क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने सडक की चौड़ाई बरकरार रखने के लिए अस्थाई अतिक्रमण हटाने के संबंध

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार में कांग्रेस की पहली लिस्ट घोषित

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें कुल 48 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं।

- पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं।

पहले चरण के लिए 21 उम्मीदवारों और दूसरे चरण के लिए 27 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। पर अभी सीट शेयरिंग का एलान नहीं हुआ है।

इस लिस्ट में पार्टी ने बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान, अजीत कुमार शर्मा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कांग्रेस नेखगड़िया से मौजूदा विधायक का टिकट काट कर चंदन यादव को टिकट दिया है। सूची में कई अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) सीटों के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है।